ASC-KSK/5.00/3O

MR. DEPUTY CHAIRMAN (CONTD.): Nishadji, this will not be treated as your maiden speech.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : सर, मेरी maiden speech नहीं, श्री संजय सेठ जी की maiden speech थी।

श्री उपसभापति : पहली maiden speech थी, यह ठीक है। So, you take five minutes more.

(उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) पीठासीन हुए)

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा जो अभिभाषण दिया गया है, उसमें सरकार की तरफ से जो कहा गया है, वे केवल असत्य वायदे हैं। आज किसान अपने को ठगा सा महसूस कर रहा है। पूरे देश का किसान तबाह व बरबाद हो गया है। नोटबंदी के बाद किसान की यह दशा हुई है कि उसका अपना उत्पादन टमाटर, मटर और आलू खेत में ही सड़ गया है, जिसके कारण लोगों ने उसको नदी, नालों और समुद्र में फेंकने का काम किया है। आज जिस तरह से कृषि उत्पाद के दाम घटे हैं, तो इससे किसान को उसका लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, जबकि पश्चिमी देशों में और अमरीका जैसे शक्तिशाली देशों में किसान की उपज के मूल्य की गारंटी ली जाती है। जो भी किसान उपज पैदा करता है, उस पर लागत और नफा लगाकर सरकार खुद उसको खरीदने का काम करती है, भले ही बाद में सरकार

उसको समुद्र में फेंकने का काम करे, लेकिन किसान को कोई घाटा नहीं होने दिया जाता है। दूसरी तरफ यहां पर बातें तो बड़ी की जाती हैं कि हम किसानों को फसल बीमा देंगे, लेकिन पूरे देश में फसल बीमे का कहीं अता-पता ही नहीं है। अधिकारी उनके आंकड़ों के चक्र में फंसे हैं, कहते हैं कि हम हर खेत को पानी देंगे। हमारे बुंदेलखंड का हाल बेहाल है। आज वहां पर पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई के पानी की समस्या है तथा अन्य जानवरों के लिए पानी की समस्या है। वहां पर सर्दियों में किसान अपनी खेती के लिए खेत में पड़ा रहता है। उसको वहां कोई बिच्छू काट लेता है, सांप काट लेता या कोई पागल सियार काट लेता है। वहां इस तरह की तमाम घटनाएं हो रही हैं। मान्यवर, इस अभिभाषण में बुंदेलखंड का कोई उल्लेख नहीं है और न ही बजट में है।

मान्यवर, जिस तरह से नोटबंदी आई और सरकार ने online के लिए ATM और Paytm के बारे में कहा कि इसका प्रयोग करो, तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आप स्वच्छता अभियान में अरबों- करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। एक तरफ तो आप बता रहे हैं कि आपको कहां लैट्रीन जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए और दूसरी तरफ आप ATM और Paytm के बारे में कह रहे हैं। वह आदमी कैसे ATM और Paytm ऑपरेट कर पाएगा, जिस आदमी को आप सिखा रहे हो कि कहां लैट्रीन के लिए बैठना चाहिए और कहां नहीं बैठना चाहिए? जब तक देश में हर आदमी के पास अपना मकान नहीं होगा, हर आदमी शिक्षित नहीं होगा, हर आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक यह कैसे संभव होगा? इस समय देश का नौजवान परेशान है और वह

अपनी दिशा से इधर-उधर धूम रहा है। देश में नोटबंदी के बाद से जितने धंधे व कुटीर उद्योग-धंधे थे, वे सारे के सारे उद्योग-धंधे बंद हो गए हैं। गुजरात से लेकर नोएडा, गाजियाबाद, मुम्बई और सूरत सभी जगह रोजगार बंद हो गए हैं। आज करोड़ों लोग बेरोजगार होकर अपने घरों में चले गए हैं। आज उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। माननीय मंत्री जी 'मनरेगा' की बात कर रहे थे, आज 'मनरेगा' का भी बुरा हाल है। आप 'मनरेगा' को फंड दे नहीं रहे हैं। आज उसमें इतनी परेशानियां हैं कि जब तक टेक्नीकल इंजीनियर उसका एस्टिमेट नहीं बनाएगा, उसकी MB नहीं करेगा और बिना पैसे के वह MB नहीं करता है, वह बिना पैसों के एस्टिमेट नहीं बनाता है, तो फिर कैसे यह सफल होगा? कैसे लेन-देन सफल होगा? उसकी पादर्शिता के लिए नियम बनाना चाहिए।

मान्यवर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसान बेहाल है, परेशान है और तमाम चीजें हैं, मैं यहां अपनी मोटी-मोटी बातें रखना चाहूंगा। हम लोग यहां उनको बार-बार उठाते हैं। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कश्यप, कहार, निषाद,केवट, मल्लाह,धीमर और तिराह को परिभाषित करने के लिए कई बार भारत सरकार को संस्तुतियां दी हैं। पूरे देश में तमाम पिछड़ी जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं। यह भारत सरकार का काम है कि वह इनकी विसंगतियां दूर करे। चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे मध्य प्रदेश है, चाहे महाराष्ट्र, चाहे बिहार और छत्तीसगढ़ है, सभी प्रदेशों से मांग आ रही है, प्रस्ताव आ रहे हैं, इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इन विसंगतियों को दूर करने का इंतजाम किया जाना चाहिए।

मान्यवर, आज पूरे देश में लोग परेशान और बेहाल हैं। ...(समय की घंटी)...जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है।

(LP /3p पर जारी)

LP-GSP/5.05/3p

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (क्रमागत) : जिस तरह से लोगों की आमदनी घटी है, उससे..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आपका टाइम समाप्त हो गया।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव ने 102 नंबर, 108 नंबर चलाने का काम किया है, जिसकी वजह से दस मिनट में, पंद्रह मिनट में प्रसव से पीड़ित महिला के पास गाड़ी पहुंच जाती है और अस्पताल पहुंचाने का काम करती है, वह सराहनीय कदम है। उन्होंने 100 नंबर चलाने का काम भी किया है, जिसके तहत पुलिस पंद्रह मिनट के अंदर अपराध को कंट्रोल करने का काम करती है।

सर, एक तरफ यह व्यवस्था है, दूसरी तरफ आप रेलगाड़ियों की हालत देखिए। आपके पास जाकर यात्री टिकट बनवाता है, लेकिन जिस तरह से ठूँस-ठूँस कर गाड़ी भरी जाती है, यात्री लैट्रिन के डिब्बे में घुस जाते हैं, ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, वह दयनीय स्थिति होती है, इसलिए आप उतनी व्यवस्था कीजिए, आप ट्रेन्स की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि जब आदमी पैसा देता है, टिकट बनवाता है, तो उसके बैठने का भी इंतजाम होना चाहिए, लेकिन आप आखिरी के डिब्बे नहीं बढ़ा रहे हैं, पटरी में सुधार

नहीं कर रहे हैं। रेल दुर्घटनाएँ हो रही हैं, अन्य तमाम चीज़ें हैं, आप उसका भी डायवर्ज़न करने का काम करते हैं कि किसकी वजह से हो गई? जाँच-पड़ताल कराने का काम करते हैं।

मान्यवर, इस तरह से..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : समाप्त कीजिए, आपका टाइम पूरा हो चुका है।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, आज अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। आपने ऐसा कानून बनाया है कि सात साल से नीचे सजा वाले को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने कह दिया है। बड़ा आदमी, दबंग आदमी गरीब आदमी को पीटने का काम करता है, उसके हाथ, पैर तोड़ देता है। एफ.आई.आर. लिख दी जाती है, लेकिन पुलिस उसको जेल नहीं भेज पाती है। मान्यवर, वह उसको दुबारा से पीटने का काम करता है। जहाँ पहले उसका एक हाथ तोड़ा था, अब एक पैर भी तोड़ने का काम करता है कि और जाओ, मेरी एफ.आई.आर. कराओ। मान्यवर, केंद्र को इस तरफ पहल करके कानून बनाना चाहिए। जो पीड़ित और परेशान लोग हैं, उनको मदद मिलनी चाहिए। आज जिस तरह से पूरे देश में बेरोज़गारी, महंगाई बढ़ रही है, वह चिंताजनक है। आपने कहा था कि दाल के दाम आसमान में चले गए हैं, आपने कहा था कि हम महंगाई को समाप्त करेंगे, बेरोजगारी समाप्त करेंगे ..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आप समाप्त कीजिए, आपका टाइम पूरा हो चुका है। ..(व्यवधान)..

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : मान्यवर, हमारा 18 मिनट का टाइम था। मेडेन स्पीच संजय सेठ जी ने दी थी। हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि हमने जो संशोधन दिए हैं..(व्यवधान)..

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : आपको बताया था कि आपके पाँच मिनट हैं, आपके पाँच मिनट पूरे हो चुके हैं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : हमारे वे सारे संशोधन मान लिए जाएं और मैं अपने संशोधनों पर बल देता हूं, धन्यवाद।

(समाप्त)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thank you. Next speaker is Shrimati Vijila Sathyananth; not here. Next is Shri Vijayasai Reddy.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (ANDHRA PRADESH): Mr. Vice-Chairman, Sir, I have carefully gone through the hon. President's speech but I did not find even an iota of reference to the special-category status that was promised to the State of Andhra Pradesh. Not only the special-category status but certain other assurances also, which were given by the Government at the time of division of the State and subsequently, do not find any place in the hon. President's speech. Therefore, Sir, I would like to bring the following points to the notice of the august House. In fact, I have

proposed some of the amendments and I request the august House to add the same to the Presidential Address.

In particular, Mr. Vice-Chairman, Sir, the special-category status, which has been assured to the State of Andhra Pradesh is, in fact, a sentiment of the people of Andhra Pradesh. It is a lifeline for the State of Andhra Pradesh. Sir, I would like to explain the sequence of events even at the cost of repetition. I would like to repeat some of the issues in this regard because some of the Members were not present at that time.

Sir, I would like to recall the assurance given at the time of division of the State of Andhra Pradesh by the then Prime Minister of this country in the month of February, 2014 that the divided Andhra Pradesh would be granted special-category status. This was the assurance that was given by the then Prime Minister, Manmohan Singh *ji*, on the floor of this House, and, many of the Members were present at that point of time.

(CONTD. BY 3Q/SK)

SK/3Q/5.10

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (CONTD.): And it was the UPA-II Government that was headed by Manmohan Singh*ji*. Further, Sir, on 2nd March, 2014,

the Union Cabinet passed a Resolution granting the Special Category status to the State of Andhra Pradesh and the Resolution that had been passed by the respected Union Cabinet on 2nd March, 2014 was forwarded to the then Planning Commission, which was in existence at that point of time, for implementation of the Special Category status. I draw the kind attention of the hon. Vice-Chairman, Sir. Sir, please listen to me. In fact, it is very unfortunate that most of the Ministers are conspicuously absent. I thought I would present my points when all the Ministers were present. In fact, except one or two, none of the Ministers are present here even to take note of the points which I am making.

Sir, I have two legal questions, two questions of law. In fact, the author of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, my colleague, Shri Jairam Ramesh*ji*, was here sometime back. I thought at least he would be here when I raise this issue. Sir, the question of law which I am referring to is -- in fact, I am asking the Minister, he is present here -- can a decision taken by the Union Cabinet go unimplemented? This is a question of law which I am raising in this august House. Sir, the decision that had been taken on 2nd March, 2014 and which was forwarded to the then Planning Commission for implementation, is not implemented even today. What is the sanctity of a

Union Cabinet decision then? Sir, what is the legal recourse in such a scenario? The NDA Government which took over subsequently refused to implement the decision that had been taken by the then Union Cabinet on 2nd March, 2014 on the premise that the neighbouring States are opposing it. On the one hand, the hon. Minister, Venkaiah*ji* says that the Special Category status is not *sanjeevani*, on the other hand, the Andhra Pradesh Chief Minister also says that the Special Category status is not *sanjeevani*. On some pretext or the other, the NDA Government is not inclined to implement the decision that had been taken by the then Union Cabinet on 2nd March, 2014. Further, the NDA Government says that the 14th Finance Commission has not recommended, or, the 14th Finance Commission has stated that no further Special Category status should be granted to any of the States. I am asking the NDA Government: Where is it mentioned in the 14th Finance Commission Report? Is it stated anywhere in the Report that no more Special Category status would be granted further to any of the States? To the best of my knowledge, the 14th Finance Commission has merely stated that it has not made any distinction between the Special Category States and the other States in so far as Post-Devolution Revenue Deficit Grants are concerned. This is the only reference that has been made

in the 14th Finance Commission's Report. This NDA Government has not implemented it on the pretext that the 14th Finance Commission has opposed it and the neighbouring States are opposing it, and the Planning Commission which was in existence at that point of time -- in fact, the Planning Commission was still in existence for ten months or so after the NDA Government came into force -- never implemented it.

(Contd. by YSR/3R)

-SK/YSR-AKG/5.15/3R

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (CONTD.): The Planning Commission has never implemented it. Now the question is: What is the recourse left if a decision taken by the Union Government is not implemented? Is this the regard that you are showing to the decision of the Union Cabinet? That is the question of law that I am raising on the floor of the august House.

Former Prime Minister in the month of February 2014 stated that the Special Category Status would be granted to Andhra Pradesh. In fact, Venkaiahji was in the Opposition at that point in time. He stood up and asked that the Special Category Status to Andhra Pradesh should be granted not just for five years, but it should be granted for ten years. That was his line of argument. I really do not understand why the NDA

Government, after coming to power, has taken a U-turn and refused to grant the Special Category Status to the State of Andhra Pradesh. This is another question of law.

The third question of law is this. Whatever recommendations or observations the Planning Commission or the Fourteenth Finance Commission makes, they are recommendatory in nature. They are not binding on the Government. The Government can always take a decision. My colleague, Jairam Rameshji, has come. I am very happy. In fact, he should have been here. Can I repeat the question of law? Can a decision taken by the Union Cabinet on 2nd March 2014 granting the Special Category Status to the State of Andhra Pradesh go unimplemented? What is the sanctity of the decision taken by the Union Cabinet then? This is the question of law that I am raising in the august House. Since you were not present, I am repeating it again.

SHRI JAIRAM RAMESH: Former Law Minister is also here. You can ask him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please mind your time.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Okay, Sir. I will not take much time. In fact, you have given me fifteen minutes. I will conclude within fifteen minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Thirteen minutes.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, kindly give me three-four minutes more.

Now, I come to the Special Package. Who asked for the Special Package? Where has it been mentioned that it's a Special Package? Even in September 2016, when it was announced, the Central Government never said that that was a Special Package for Andhra Pradesh. Hon. Finance Minister merely said that he was giving some concession to the State of Andhra Pradesh. What is the concession that the NDA Government is giving? In fact, there is nothing in the so-called Special Package. What is going to be given for the next five years towards the State's share from the Pool of Central Taxes, by way of devolution of funds, has been mentioned as the Special Package and then they say that this is the Special Package that is offered. Not just Andhra Pradesh, every State in India is entitled to State's share from the Pool of Central Taxes. There is nothing new or unique or extra what is being offered to the State of Andhra Pradesh. These are all the issues.

Sir, allow me to speak for five minutes more on another very important issue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Try to conclude it.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, through you, I would like to draw the attention of the former Law Minister to a very important issue. In 1985, the former Prime Minister, Late Rajiv Gandhi, who had the vision, brought 52nd amendment to the Constitution incorporating anti-defection law in the Constitution.

(Contd. by VKK/3S)

-YSR/VKK/3S/5.20

SHRI V. VIJAYASAI REDDY (CONTD.): It provided that if one-third of the Members elected from a particular party go out of the party, it would be construed as a split and, therefore, it will not attract disqualification proceedings. Subsequently, in the year 2003, depending upon the situation prevailing at that point of time, the revered leader, Shri Vajpayee, brought forward another amendment, the Constitution (Ninety-First) Amendment, providing that not one-third but two-thirds of the Members who switch over from one political party to another political party would only be construed as

a split. Not even split, it would be construed as an amalgamation of the party, and therefore, disqualification proceedings would not be attracted. Sir, I need two more minutes. I will finish. This is a very important subject. When the Congress was in power, they had taken advantage of these loopholes. When NDA has come to power, they are trying to take advantage of these loopholes. So, whichever party is in power, it always takes advantage. The very foundation of democracy is at stake today. That is why, I am requesting you to give me 2-3 more minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I cannot extend time again and again. Please conclude now.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, you are affected; I am affected; everybody here is affected. I will tell you why. How is the power vested with the Speaker? Para 6 of the Tenth Schedule says that the power is vested with the Speaker. Further, Para 7 of the Tenth Schedule — and I am also referring to Article 212 of the Constitution — says that any proceedings relating to disqualification would be construed as Parliamentary or Legislative proceedings. Therefore, the courts are barred from interfering in the proceedings. This is the status now. In the light of this scenario, the elected representatives from many political parties other than the ruling dispensation

switch over freely, taking bribe or money and switching over parties and switching over loyalties. Bravely and blatantly, they switch over the party. Speakers of the respective Assemblies are not in a position to take a decision because there is no provision that has been incorporated either in 52nd Amendment or 91st Amendment. Therefore, there is a necessity as of today to introduce an amendment to plug that loophole stipulating a time limit within which the Speaker has to dispose of the disqualification petition filed before him. I request the august House to take note of it and then, implement it immediately. I also request the Government. Former Law Minister is present. In fact, he should have dealt with the situation. In fact, when they were not in power, they were also the sufferers. He should remember that. Sir, I have one more issue. It is the final issue.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): No more issue. You will have another occasion to speak.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, I will just refer to it and then leave it. It is about women reservation. This is a very, very important issue. Women Reservation Bill which was passed by this august House and sent to Lok Sabha had lapsed on account of dissolution of Lok Sabha. For the Government of the day, the NDA Government, there is every necessity today

to implement it in order to empower the women and then, bring it into force immediately. I would have spoken much more on this. Since you are not allowing me to make my submissions, I conclude my speech. Sir, I am thankful to you.

(Ends)

(Followed by BHS/3T)

-VKK/BHS-RPM/3T/5.25

SHRI JOY ABRAHAM (KERALA): Sir, I thank you very much for giving me this opportunity. The President's Address to the Joint Session of Parliament is a Constitutional obligation. The Governors also have this Constitutional obligation to make an Address in the Legislative Assemblies. Unfortunately, this has become a mere ritual. The President is supposed to give new policies and vision of the Government for the next financial year. Now, the Address is just a mere narration of the programmes one by one. There is no new policy statement. Except a reference regarding simultaneous elections I did not find any other point, any new policy or vision embedded in the Address. It is unfortunate that various schemes are depicted in Hindi only. My learned friend Mr. Yechury has numbered some twelve or thirteen Prime Minister's schemes. All these schemes are known by their name in Hindi

only. I come from a non-Hindi State. I am not against Hindi. I know to read and write Hindi but I am not proficient. All our national schemes, all Central schemes are named in Hindi. No English equivalent is given there. For '*Swachh Bharat*', there is 'Clean India'. So, my humble submission is, for every scheme of the Central Government, if it is in Hindi, there should be an English equivalent to the schemes. Every scheme should be known to the masses by their literal meaning. If a person is not proficient in Hindi, he cannot understand the real, literal meaning of the words. So, I repeat my submission that all the Central schemes should be supported by an equivalent English name so that the masses can understand its full implications.

At the outset, the President says that this is a historic Session. His argument is based on the advancement of the Budget cycle and merger of the Railway Budget. That is why he said that it is a historic Session. But, I think, it will remain as a tall claim without proof of its advantages. The former Railway Minister and the former Law Minister are here. I think, the Railway Budget is sidelined. There are just some references. It is a public utility service and needs a special consideration. I think so. Therefore, there should be a separate Railway Budget in future.

In paragraph 16, a very rosy picture of the climatic condition of the nation is depicted. The President ought to have mentioned the drought situation in South India, especially, in the Southern States of Tamil Nadu, Kerala etc. (Contd. by DC/3U)

DC-PSV/5.30/3U

SHRI JOY ABRAHAM (CONTD.): The hon. President has given a rosy picture of good crops, good monsoon and good rain. But the fact is that, Tamil Nadu, Kerala and other Southern States are reeling under drought.

Then, para 55 says about demonetization. It says that demonetization was aimed to combat the evils of black money, corruption, counterfeit currency and terror financing. Demonetization was a bold step. I will not question its *bona fides*. But one thing is clear; the rationing of currency was not anticipated. I think, even by the Government, there was not sufficient preparation. There was not sufficient foresight. So, for the common man, it was a tragedy and the common man suffered the most. I again refer Mr. Yechury. Somebody claimed that it was a surgical strike. To compare demonetization with surgical strike is really an insult to our Armed Forces and their supreme sacrifices. Demonetization has not the essential ingredients of a surgical strike. A surgical strike has its own ingredients.

One is, maximum destruction of the target with minimum casualty on the striking side. Here, unfortunately, the target may be black-money, the target may be fake currency, the target may be corruption, but, unfortunately, the target was the common man and the common man was the casualty. We saw long queues, several hardships and currency rationing. So please don't compare this move with surgical strike. That is my point. Actually the common man suffered the brunt of demonetization. I was hearing the arguments from Shri Ravi Shankar Prasad too; I am sorry to say,-- we have to support the Motion expressing thanks to the President's Address; that has also become a ritual--but I can't find any merit in Shri Ravi Shankar Prasad who moved the motion. Thank you very much.

(Ends)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Dr. Satyanarayan Jatiya.

डा. सत्यनारायण जटिया (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण सरकार के पिछले साल के, 2016-17 के कार्यकरण का एक तरह से लेखा-जोखा है। इसका संबंध उसके सामाजिक सरोकारों से है, उसके आर्थिक प्रबंधनों से है, विकास कार्यों से है, वैदेशिक नीतियों से है और कुल मिलाकर यह राष्ट्रहित में

किए गए कार्यों का एक विवरण है। इसके साथ ही साथ अर्थ-संकल्प और बजट ऐसे निरंतर तीन महत्वपूर्ण विषय चर्चा में आए हुए हैं।

मैं जानता हूँ कि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण है, उसका आरम्भ ही अत्यंत सुन्दर तरीके से किया गया है। "नूतन और नवजीवन की प्रतीक वसंत ऋतु" से अभिभाषण की शुरुआत हुई है। हम जानते हैं कि जब वसन्त ऋतु आती है, तो पुरानी चीज़ें जाती हैं और नयी बातें आती हैं। जो पुराना है, उसको छोड़ना और जो नया है, उसको स्वीकार करना होता है। विसंगतियाँ और चुनौतियाँ होती हैं। इन्हीं बातों को यदि हम कहें, तो निश्चित रूप से इसको ऐसा कहा जा सकता है कि जो विसंगतियाँ थीं, जो चुनौतियाँ थीं, उनमें से भी हमने कुछ अच्छा निकालने की कोशिश की है।

(उडब्ल्यू/वीएनके पर जारी)

VNK-KR/3W/5.35

डा. सत्यनारायण जटिया (क्रमागत) : यदि माननीय अटल जी के शब्दों में कहा जाए, तो हम यह कह सकते हैं :-

"टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर,
पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर,
झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात,
प्राची में, अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ,
गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।"

वैसे ही एक नव विहान के लिए, एक नई संरचना के लिए सरकार ने जो काम करना आरंभ किया, उसकी परिणति होती हम देख रहे हैं। हमारा जो लोकतंत्र है, जिसको कहा गया है कि "हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए" जो-जो चीजें आवश्यक हैं, उन-उन बातों को करते जाना है। इससे धीरे-धीरे हमारा देश आगे बढ़ता जाता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में, जो सरकार ने कदम उठाए हैं, उनकी अभिव्यक्ति राष्ट्रपति के अभिभाषण में मिलती है। इसमें कहा गया है, 'सबका साथ, सबका विकास'। यह 'सबका साथ, सबका विकास' ही हमारा लोकतंत्र है। सबको साथ में लेकर, सब समाज को साथ में लेकर आगे बढ़ते जाना है। हमारा जो यह उदात्त लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए हम जो विविध उपाय करते हैं, उसमें सबका विकास अंतर्निहित होता है। हमारे यहां सूत्र में कहा गया है, "सं गच्छध्वं सं वदध्वम्",

"देहि शिवा वर मोहि इहै, शुभं करमन ते कबहूं न टरूं,

न डरूं अरि सौं जब जाइ लरूं, निसचै कर अपनी जीत करूं..."

जो सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है, उसको करना एकदम आसान काम नहीं था या एकदम निर्णय की हुई बात नहीं थी। "शठे शाठ्यम् समाचरेत", जैसे को तैसा करना चाहिए, इसलिए जो कुछ हमारे लिए अनुकूल नहीं था, यदि कुछ हो गया है, तो उसका जवाब तो देते आना चाहिए। मैं कह सकता हूँ :-

"सबसे बड़ा धर्म है नर का, सदा प्रज्ज्वलित रहना,

दाह की शक्ति समेत स्पर्श भी नहीं किसी का सहना।"

यदि हमें किसी ने चुनौती दी है, तो उस चुनौती को स्वीकार करने की सामर्थ्य हममें है, यह हमें प्रकट करते आना चाहिए और हमने प्रकट करके दिखाया है।

इन सारी बातों को याद करते हुए हमने दार्शनिक संत, रामानुजाचार्य को भी स्मरण किया है। यह हमारी परंपरा है और रामानुजाचार्य की परंपरा के बाद हम देखते हैं, तो पाते हैं कि उसके बाद गुरु रामानंद की परंपरा है, उसमें गुरु नानक देव हैं, उसमें संत कबीर हैं, उसमें संत रविदास हैं, मीराबाई हैं, सदना हैं, सेन हैं, तो ऐसी भक्ति की एक परंपरा है, उसको हमने हमारे दार्शनिक संत, रामानुजाचार्य जी को स्मरण करते हुए प्रतीकात्मक रूप से स्मरण किया है।

हमने चम्पारण सत्याग्रह का भी स्मरण किया है और जनशक्ति की बात कही है। यह जनशक्ति ऐसी है, जो एक वातावरण बनाती है, एक निर्माण करती है कि समाज और देश में जागृति लाने के लिए और मौका पड़े, तो उसको पूरा करने के लिए, सभी बातों के लिए, त्याग करने के लिए उदात्त रहने का जो एक वातावरण होता है, उसी को हम जनशक्ति कहते हैं। उसी को करने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने जब आह्वान किया, तो देश उसका पालन करने के लिए तत्पर हुआ, क्योंकि जिस व्यक्तित्व में त्याग, तपस्या होती है, उसका अनुसरण करने के लिए वह जो जनशक्ति होती है, वह ऐसे ही पैदा होती है और उसके कारण से उन बातों को पूरा करने के लिए जब कहा गया है कि आपको अपनी गैस की सब्सिडी को छोड़ना है, तो लोगों ने आगे

आकर उसको छोड़ने का काम किया है। इस तरह से 1 करोड़ 2 लाख उपभोक्ताओं को गैस सब्सिडी के रूप में जो केन्द्रीय सहायता मिलती थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया है।

(3एक्स/एनकेआर-केएस पर जारी)

NKR-KS/3X/5.40

डा. सत्यनारायण जटिया (क्रमागत): उसका लाभ गरीब वर्ग के व्यक्तियों को, वंचित वर्ग के व्यक्तियों को मिला। इसमें निश्चित रूप से माननीय प्रधान मंत्री जी में जो नैतिक बल था, उस बल का प्रगटीकरण हुआ है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 'स्वच्छ भारत अभियान' की, जो अब जन-आन्दोलन में बदल गया है, जब प्रतीकात्मक शुरुआत होती है, अभी हमारे लोग कह रहे थे कि प्रतीकात्मक झाड़ू लगाने से क्या हो गया? जब कोई ऐसा व्यक्ति जो देश का नेतृत्व करता है और झाड़ू लगाता है तो वह संदेश देता है कि हमें भारत को स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है और यह अभियान निश्चित रूप से सारे भारत में फैल गया है। गांवों में जिस प्रकार से खुले में शौच करने को वर्जित करने के लिए उपाय किए गए हैं, लोगों ने स्वतः उसे स्वीकार किया है। किसी राष्ट्र के निर्माण में जनशक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

"हम करें राष्ट्र आराधन,
तन से, मन से, धन से,
तन-मन-धन जीवन से।"

अगर जीवन में हमें कोई शुरुआत करनी है तो अपने आपसे करनी होती है। इसलिए प्रधान मंत्री जी ने एक अच्छे आन्दोलन की शुरुआत की है, जिसे अब आगे ले जाया जा रहा है।

अभिभाषण के पैरा 5 में, गरीब वर्ग के दलित, पीड़ित, शोषित और वंचित वर्ग के लोगों के बारे में कहा गया है, किसानों के बारे में कहा गया है, श्रमिकों के बारे में कहा गया है, युवाओं के बारे में कहा गया है। इसलिए इन सारे लोगों का कल्याण ही लोक-कल्याणकारी राज्य का, लोकतंत्र का हमारा लक्ष्य है। इसे पूरा करने के लिए हमने एक संकल्प लिया है -

"मानवता के लिए ऊषा की किरण जगाने वाले हम,

शोषित, पीड़ित, दलित जनों का भाग्य बनाने वाले हम।"

ऐसा संकल्प लेकर सरकार ने काम किया है।

"कौन बनाता हिन्दुस्तान,

भारत का मजदूर किसान।"

इसलिए भारत के मजदूर और किसानों की सुध लेने वाली बात राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कही गई है, जो निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है।

जनधन योजना के बारे में कहा गया है कि गरीब आदमियों का खाता बैंकों में कैसे खुलेगा, ऐसा कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन जन-धन योजना जब आरम्भ की गई और खाते खुलने का काम हुआ तो 26 करोड़ लोगों तक इस योजना को पहुंचाने का काम इस सरकार के समय में हुआ है। जन-धन योजना से जन-सुरक्षा की गतिविधियां

प्रारम्भ हुई हैं और 13 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में लाया गया, जो निश्चित रूप से अभिनव प्रयास है। हम आलोचना करने के लिए, समालोचना करने के लिए, समीक्षा करने के लिए सभी बातों का सहारा ले सकते हैं, परन्तु जो कदम अच्छे उठाए गए हैं, उनकी सराहना करने का काम भी होना चाहिए, करना चाहिए। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी और इस सरकार की जो योजनाएं थीं, जो पिछले वर्ष साकार हुईं, उन सबका वर्णन अपने अभिभाषण में किया है।

भारतीय डाक भुगतान बैंक के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है। निश्चित रूप से जहां-जहां भी पोस्ट ऑफिस हैं, वे सब अब बैंकिंग का काम भी करेंगे। प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के बारे में दो लाख करोड़ रुपए के 5.6 करोड़ ऋण उपलब्ध कराए गए, जिसमें ऋण लेने के लिए किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होगी। पद 8 में इस योजना को शामिल किया गया है।

इस तरह निश्चित रूप से हर प्रोग्राम का कुछ-न-कुछ वर्णन इस अभिभाषण में हैं। दीनदयाल अन्त्योदय योजना, स्वास्थ्य समीक्षा योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें डेढ़ करोड़ परिवारों को गैस कनैक्शन देने का प्रावधान किया गया है, उसमें 37 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग शामिल हैं।..(व्यवधान).. मेरे लिए शायद 10 मिनट हैं। आप जितना समय देना चाहें।..(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : 10 मिनट हो चुके हैं।

डा. सत्यनारायण जटिया : मुझे पता नहीं चला, कब 10 मिनट हो गए? कोई दिक्कत नहीं है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अतिरिक्त इन्द्रधनुष योजना में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा की बात कही गई है। इसी प्रकार से कृषि और किसानों को समर्पित खड़ी फसलों के लिए जो योजना शामिल की गई है, उन्हें सहायता देने का प्रावधान किया गया है, उनके लिए बीमा की व्यवस्था की गई है और मध्य प्रदेश में फसल बीमा योजना को हमने काफी सफल रूप से चलाने का काम किया है और उससे काफी लोगों को फायदा पहुंचा है। किसान क्रेडिट कार्ड और सिंचाई के लिए, हर फसल और देश में दालों की कमी को दूर करने का प्रयास हुआ है। इसमें सरकार की सारी योजनाओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार के उपाय किए गए हैं। नारी शक्ति के बारे में - "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः" - नारी शक्ति के सम्मान और खेलों की प्रतिभा के बारे में कहा गया है। हमारे पास जो राष्ट्रीय खेल विकास निधि है, एन.एस.डी.एफ. है, उसे विकसित करने की बात हमारी सरकार करने वाली है। बच्चों में, स्त्री-पुरुष की जो विविधता थी, असमानता थी, उसे दूर करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक बढ़ाने का काम, युवा ऊर्जा के बारे में, हर हाथ को हुनर और काम देने के लिए कौशल विकास की बात और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 951 रोजगार कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित करने की बात शामिल है। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय कौशल केन्द्र के रूप में, वस्त्र परिधानों में, नए रोज़गार सृजन करने के लिए

- श्रमेव जयते - क्योंकि श्रम के बिना कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए श्रम को महत्व देने का काम हुआ है। ..(व्यवधान).. मैं एक-दो मिनट और लेना चाहूंगा।

(3Y/DS पर जारी)

DS-RSS/5.45/3Y

डा. सत्यनारायण जटिया (क्रमागत) : लोग काले धन के बारे में बड़ी-बड़ी बातें करते थे कि भ्रष्टाचार मिटाना चाहिए, लेकिन वह हुआ क्यों नहीं? क्योंकि किसी ने किया नहीं, परन्तु प्रधान मंत्री के साहसिक निर्णय के बाद हमने देखा है कि इस ओर जिस तरह का प्रवाह हुआ है, उसे पूरा देश देख रहा है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके परिणाम सुखद और लोगों के लिए सुरक्षात्मक होने वाले हैं, वह सारा पैसा गरीबों को कम ब्याज पर मिलने वाला है, उसके कारण काफी ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता) : धन्यवाद, आपका टाइम समाप्त हो चुका है।

डा. सत्यनारायण जटिया : सर, अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार की सारी योजनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ।

"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्।"

सभी सुखी हों, सभी निरोग, कोई न पावे दुःख-शोक, ऐसी शुभ-भावना के साथ, राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

(समाप्त)

श्रीमती रजनी पाटिल (महाराष्ट्र) : सर, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर मैं बहुत ही कम शब्दों में अपने विचार यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ, उसमें हमें यह अपेक्षा थी कि वह अभिभाषण सभी को लेकर होगा, क्योंकि वे बार-बार बोलते हैं कि "सबका साथ, सबका विकास।" अभी जटिया जी *"सर्वे भवन्तु सुखिनः"* की बात कर रहे थे, लेकिन जिस समाज में सब लोग साथ में रहते हैं, उसी समाज में सिर्फ चंद लोगों को साथ में लेकर और कुछ लोगों को बाजू में रखकर हम आगे नहीं जा सकते, यह हमें सिखाया गया है और यह कांग्रेस की राजनीति है।

सर, मैं आपके माध्यम से यहाँ से यह बोलना चाहूँगी कि काले धन का बार-बार जिक्र किया जाता है। यहाँ पर प्रधान मंत्री हों या अर्थ मंत्री हों, वे कृपा करके इस सदन में हमें आँकड़े दे दें कि उन्होंने जो नोटबंदी का निर्णय लिया, उसकी वजह से कितना काला धन वापस आ गया, टेररिज्म कितना कम हो गया? अगर उसके आँकड़े हमें मिल जाएँ, तो हम आपके बहुत आभारी रहेंगे।

सर, राष्ट्रपति जी ने रसोई गैस के बारे में बोला है कि "ऊर्जा स्कीम" शुरू की गई है और बहुत ही भारी पैमाने पर हमने रसोईघर में गैस पहुँचाने का काम किया है। मैं तो समझती हूँ कि इन्होंने जितना खर्चा गैस पहुँचाने के लिए किया, उससे कहीं ज्यादा खर्चा एडवर्टाइजमेंट पर किया। आप किसी भी पेट्रोल पम्प पर जाइए, वहाँ आपको प्रधान मंत्री, मोदी जी का फोटो और "गैस की सब्सिडी छोड़ो" लिखा हुआ मिल जाएगा। इस तरह से इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट करके खुद का बहुत बड़ा बोलबाला यहाँ पर कर दिया है। खुले में शौच के बारे में बहुत एडवर्टाइजमेंट होती है, लेकिन

आज भी जमीनी हक़ीकत यह है कि खुले में शौच हो रहा है, गाँव-गाँव में हो रहा है। मेरे ऐसा कहने का मतलब यह नहीं है कि यह बात अच्छी है, लेकिन खुले में शौच से निपटने का अभी तक बंदोबस्त नहीं हुआ है।

सर, सबसे ज्यादा मैं तीन मुद्दों के ऊपर बात करना चाहूँगी। मैं सबसे पहले किसान का मुद्दा यहाँ उठाना चाहती हूँ। आज देश का किसान बहुत ही बदतर हालत से जूझ रहा है। जिस समय नोटबंदी का फैसला हुआ, उस समय बहुत सालों के बाद हमारे मराठवाड़ा क्षेत्र में बारिश हुई थी और बारिश के बाद हमें लगा था कि कम से कम अब हमारे अच्छे दिन आ जाएँगे, लेकिन दुर्भाग्य से जब 8 नवम्बर को नोटबंदी का निर्णय हो गया, जब हमारी खरीफ की फसल बाजार में जानी थी, तब उसकी आधे से भी कम कीमत हमें मिली और हमारे सामने परेशानी की परिस्थिति पैदा हो गई।

(श्री उपसभापति पीठासीन हुए)

सर, तब रबी का सीज़न शुरू हो गया था और जब रबी के लिए हमें बीज बोना है, बीज लाना है और हमें खेती के कई प्रकार के काम करने हैं, उस समय रबी के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था, ऐसी हमारे किसानों की हालत हो गई थी। आज जब बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय वहाँ के किसानों के लिए ढोल बजा-बजाकर यह कह रही है कि हमें चुनकर लाइए, हम किसानों का कर्ज़ा माफ कर देंगे, तो यह सुनकर मुझे बहुत हँसी आती है। हम इतने दिनों से यह माँग कर रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र में, जहाँ किसानों की सबसे ज्यादा आत्महत्याएँ हो रही हैं, वहाँ पर आपने उनको राहत नहीं दी। ऊँट के मुँह में जीरे के समान हमारे कर्ज़े के सात दिन का ब्याज माफ करने का ऐलान

करके अर्थ मंत्री ने किसानों का मज़ाक उड़ाया है। यह बहुत बुरा लगता है। आप कहते हैं कि यूपी में सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज़ा माफ करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार आ चुकी है। वहाँ के लोगों ने तो आपको चुन लिया है, तो वहाँ के किसानों का कर्ज़ा आप क्यों नहीं माफ करते? सर, हमारी मराठी में एक बहुत ही अच्छी कहावत है। मुझे मालूम नहीं कि उसको हिन्दी में कैसे बोला जाता है। वह कहावत है- "लबाडा घरचा आवतण, जेवल्या शिवाय खरं नाही।" जब किसी के मन में खोट होती है और अगर वह खाने पर बुलाता है, तो जब तक खाना नहीं मिलता, तब तक उस खाने का मतलब नहीं है, उसके मन में खोट है, ऐसा हम समझते हैं। इसलिए ये सिर्फ बातें करते हैं।

(3जेड/एमसीएम पर जारी)

MCM-KGG/3Z/5.50

श्रीमती रजनी पाटिल (क्रमागत) : इसलिए ये सिर्फ बातें करते हैं कि यह देंगे, वह देंगे, अलग-अलग योजनाएं हैं, इस प्रकार ये बड़े-बड़े शब्द बोलते हैं। यह मानना पड़ेगा कि बी0जे0पी0 ये शब्द कहां से निकाल कर लाती है? इस तरह से लोगों को कुछ ऐसा बताते रहते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, यह मैं आपको बताना चाहूंगी।

सर, मैं दूसरी बात महिलाओं के बारे में करना चाहूंगी, जिसका जिक्र अभी अहमद पटेल जी ने भी किया था। मैं बताना चाहूंगी कि हम बहुत आशा से देख रहे थे, इस सरकार को 3 साल होने को आए, जबकि सरकार में आने से पहले इन्होंने एक

आश्वासन दिया था कि हमें चुन कर भेजिएगा, हम महिलाओं को आरक्षण देंगे। हम महिलाओं को 33 परसेंट आरक्षण लोक सभा में देंगे, राज्य सभा में देंगे, विधान सभा में देंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। देश की सब महिलाओं को लगा था कि शायद यह बदलाव हो सकता है, शायद मोदी जी यह बदलाव कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं के लिए कोई भी राहत इस सरकार ने नहीं दी। हमारे राजीव गांधी जी ने पहली बार पहल करके 33 परसेंट आरक्षण पंचायत राज के माध्यम से हमें दिया था। आज हम यहां पर आकर बोल रहे हैं तो उसका अगर कोई कारण है तो सिर्फ राजीव गांधी जी हैं। मैं जिला परिषद से आई हूं। राजीव गांधी जी के आरक्षण के तहत मैं चुनकर आई हूं और उसके बाद में लोक सभा, फिर राज्य सभा, यहां तक आने का जो मेरा फासला है, वह राजीव गांधी नहीं आते तो हम यहां तक कभी नहीं आ सकते थे, यही मुझे मानना पड़ेगा। यह आरक्षण का जो मसला है, यहां पर इन्होंने हमें सिर्फ कागज के फूल दिखाने का काम कर दिया है।

मैं लास्ट में इंदिरा जी के लिए बोलना चाहूंगी। इन्होंने जन्म शताब्दी मनाने की बात की है। लेकिन जिस इंदिरा गांधी जी ने देश पर इतने साल राज किया, जिस इंदिरा गांधी जी को पूरे विश्व में ऑयरन लेडी के रूप में पहचाना जाता है, अमेरिका जैसे देश में कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बन सकी, लेकिन वह चमत्कार हमारे देश ने कई साल पहले किया है, लेकिन ये लोग इंदिरा गांधी जी का नाम भी लेना भूल जाते हैं, उनको भी सौ साल इसी वर्ष हो रहे हैं। उनका इस बारे में जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। पंडित जी का भी नाम भूल गए। वे अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम

भूल गए और राजीव गांधी जी का भी, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, उनका भी नाम भूल गए। उनको ऐसा लगता है कि इन लोगों का नाम लेने से लोगों को फिर वह स्मृति याद आएगी, यानी स्मृति इरानी नहीं। उनकी स्मृति से उनके जो विचार हैं, वे उनके ज़ेहन में आ जाएंगे। फिर अगर लोगों के ज़ेहन में इंदिरा जी का नाम, राजीव जी का नाम, नेहरू जी का नाम, गांधी जी का नाम आ गया तो फिर होगा कि लोगों का दिमाग कांग्रेस के प्रति कुछ विचलित हो सकता है। इस भय से ये उनका नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से इतिहास बदलने से, इस तरह से इतिहास मिटाने से उनका नाम नहीं मिट जाएगा। उनका काम इतना बड़ा है, उनकी शहादत इतनी बड़ी है कि चाहे इंदिरा जी का नाम न भी लें, तो भी हर घर में इंदिरा जी और जो भी यहां बैठे हैं, उनके भी घरों में मालूम हुआ कि अगर इंदिरा जी का नाम लिया तो हरेक के घर में इंदिरा गांधी जी के लिए क्या भावना होगी, वह मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। इतना छोटा मन दिखाकर जो बड़ा होता है, जो राज करता है, जो राजकर्ता करके बोलता है, उसका हृदय भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये लोग छोटी-छोटी चीजों में अपना मन छोटा दिखाते हैं। नेहरू जी का नाम जान-बूझ कर नहीं लेंगे। हर कोई जो फ्रीडम मूवमेंट से बड़ा नेता बना है, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार वल्लभभाई पटेल, जो हमारी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हरेक को अपनी तरफ खींचने की ये लोग कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, मेरे खुद के नाना जी हुतात्मा विष्णु गणेश पिंगले, जिन्होंने गदर मूवमेंट में हिस्सा लिया था, जिनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था, उनको भी हमारे यहां के सांसद ने बोला कि ये तो आर0एस0एस0 की तरफ के हैं। तो इस तरह

से इनके यहां कोई धरोहर नहीं है, न उनके यहां कोई परम्परा है, न उनको पता है कि स्वतंत्रता सेनानी का क्या मतलब होता है। इसलिए हर कोई स्वतंत्रता सेनानी या बड़े व्यक्ति के साथ अपने को जोड़ना चाहते हैं।

इतना ही नहीं, नोटबंदी के टाइम पर जो लोग लाइन में लगे थे, उस समय कुछ लोग मर गए थे। उनके लिए हमारे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि ये लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनको इतना भी समझ में नहीं आता कि स्वतंत्रता सेनानी का क्या मतलब है? ऐसे लोगों को श्रद्धांजलि देने का मन भी इनके पास नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कह कर अपने भाषण को समाप्त करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर इन दो-तीन चीजों का राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया होता तो अच्छा होता। खास करके महिलाओं को आरक्षण देने की आवश्यकता है। सर, आपने मुझे मौका दिया, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के ऊपर, मैं उनका स्वागत करते हुए अपने भाषण को समाप्त करती हूं।

(समाप्त)

(4A/KLS पर आगे)

KLS/4A-5.55

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you for adhering to the time. Mr. Dharmapuri Srinivas, when your name was called, you were not here. So, you can speak now.

SHRI DHARMAPURI SRINIVAS (TELANGANA): I thank you very much for the opportunity given to me. I also apologize that I was not present when you called me earlier. At the outset, I express my thanks to His Excellency, the President of India for his Address to the Joint Session of Parliament. But I am absolutely disappointed with the raw deal given to the State of Telangana. The Government has declared its intention to carry everyone with it, *sab ka saath, sab ka vikas* wherein the guiding principle is cooperative federalism. In the process the Union Government expects the cooperation of the various States also. In fact, though we are not a part of the NDA, yet our Chief Minister supported the Government and the Prime Minister on various occasions, more so at the time of demonetization in the larger interest of the nation though it caused setback to common man. Now, coming to Telangana, it is a fledgling State. It needs best nourishment and care. At this juncture, Telangana State is lucky in having an eminent visionary like Chandrashekar Raoji, a leader who knows the ins and outs and each nook and corner of the State as its Chief Minister, a right leader at the right time. Nevertheless the helping hand of the Union Government is very much needed at this hour to rebuild the State which has been formed after 60 long years of struggle. I am confident that the Union Government would

in its magnanimity lend its helping hand to the State of Telangana for its development. Yet despite umpteen setbacks, the down to earth Chief Minister took big strides towards the development of the State in all directions, both in development and welfare in the last two-and-a-half years. We are the top State in development. While extending top priority to irrigation and drinking water, other welfare schemes too have been accommodated in the State Budget. I am talking about the State Budgets, during the last three years, with ultimate prudence, which the entire nation is hailing. Our aim and basic idea is to complete the irrigation projects as early as possible so that the resultant bounty could be diverted to other welfare schemes. To quote a few of Telangana State Government's priorities, I may mention that being a new State, it is taking up so many schemes so fast. We are able to implement them. I only wish that the Government of India watches it and help the State Government accordingly. We have Mission Kakatiya for irrigation and Mission Bhagiratha to provide drinking water to every household. These two schemes are very popular. Chief Ministers of various States and other leaders visited our State and announced their intention to start such schemes in their States also. Then we have the schemes like Double Bedroom Houses which is very appreciable. We have

Aasara monthly pension at the rate of Rs.1000/- for about a crore of beneficiaries in the State. As far as marriages in poor families are concerned, *Shaadi Mubarak* and *Kalyana Lakshmi* schemes are there to provide assistance to poor people of all religions. We have residential schools for minorities, SCs, STs, BCs and OBCs. We are also going ahead with the infrastructure development to provide free education to the poor from KG to PG. We have many more such schemes. Within two-and-a-half years of the State formation, I am happy to say that under the dynamic stewardship of Shri KCR, our State has emerged as the most happening State.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Srinivasji, how many more minutes do you want to speak?

SHRI DHARMAPURI SRINIVAS: Maybe, two minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then ...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Is he speaking on the Motion of Thanks to the Governor or the President?

(Followed by 4B/SSS)

SSS-GS/6.00/4B

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. We will extend until he finishes and then your statement will be laid. Okay, Shri Srinivas, please proceed.

SHRI DHARMAPURI SRINIVAS: Power cuts have become a thing of the past and many investors are enthusiastically coming forward to start their business in our State. Now, it is time for the Union Government to fulfill the promises made in the State Reorganisation Act. But at this crucial juncture, when a liberal allocation of funds is rightly due to the State, the Union Budget 2017-18, presented the other day, have plunged us in to utter disappointment. Our aspirations are shattered as we got a raw deal despite the fact that our Chief Minister supported the Centre in all times of need. The following issues of importance call for urgent action: The two-and-a-half years time is too long a period for bifurcation of the High Court. Andhra Pradesh Chief Minister has shifted ninety per cent of his offices to Andhra Pradesh Capital, Amaravathi. It is not at all difficult for them to identify a building for a High Court. I appeal to the Union Government to take serious steps in this direction because it is a State and High Court has to be there. I also appeal to the hon. Prime Minister to consider adoption of 'Kaleshwaram Irrigation Project' as a National Irrigation Project. I reiterate our appeal to

fulfill all commitments made in the State Re-organization Act. An increase in the number of Assembly seats would greatly help devolving powers at the grassroots. Hence, there is a need to consider our request to increase the Assembly seats. We are happy that some of the Union Ministers, other State CM's appreciated our initiatives and even they are in a mood to adopt these initiatives in their respective States also. With a heavy heart I am constrained to express our utter disappointment once again at the Union Budget regarding the raw deal extended to Telangana. We still hope that the deficiency will be compensated in a different form, in this Session itself, in the supplementary allocations by the end of the Budget Session. While I conclude, I would like to say that no mention has been made about the OBCs in the President's Address and I also request the Government of India, the Prime Minister especially, to consider forming a separate Ministry for the OBC's.

While I conclude, I reiterate my profound thanks to His Excellency, the President of India for his Address to the Joint Session and I emphasise once again that our party would extend its full support to all the people-friendly endeavours. I appeal to the Government of India to take into consideration the development of the State of Telangana. It has a very big history and a

struggle behind it because I feel they should feel responsibility to see to it that proper sanctions are made. We were all expecting that AIIMS would be announced for Telangana. So, as I said, there is a raw deal given to us. These things should be taken into consideration. Thank you, Sir.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up the Statement by Minister.

* STATEMENT RE. NEGOTIATIONS IN 28TH MEETING OF PARTIES TO MONTREAL PROTOCOL HELD IN OCTOBER, 2016 IN KIGALI, RWANDA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): Sir, with your permission, on behalf of the Minister of State of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Shri Anil Madhav Dave, I rise to lay on the Table of the House a Statement in English and Hindi in today's Supplementary List of Business.

Sir, I rise to make a *suo motu* statement on the recent negotiations held under the Montreal Protocol for control of ozone depleting

.....

*** Laid on the Table.**

substances that was held in Kigali, Rwanda from 6th to 14th October, 2016, and in which I participated. The 28th Meeting of Parties to the Protocol held in Kigali adopted an amendment to the Protocol which is historic and aimed at phasing down the Hydrofluorocarbons (HFCs) that contribute to global warming.

I would like to inform the august House that HFCs do not deplete the Ozone layer. However, they have high global warming potential. The amendment to Montreal Protocol agreed in Kigali has facilitated the creation of an international regime of regulatory actions and financial support for treating this set of chemicals in the same manner and with the same urgency as was accorded to other Ozone Depleting Substances in the past.

Mr. Deputy Chairman, Sir, it is significant to note that the negotiations for phasing down of HFCs under the Montreal Protocol were initiated way back in 2009, but these negotiations gathered momentum only after India submitted an amendment proposal for phase down of HFCs under the Montreal Protocol in April, 2015. The Indian Amendment proposal was crafted in a way to balance the needs of our rapidly growing economy and achieve maximum climate benefit.

Notably, India represents only around 2 per cent of the global production and consumption of HFCs but our manufacturing and consumption sector is expected to grow at a rapid pace in future. Our challenge, therefore, was to secure international agreement on a regulatory regime that served the global expectations and yet protect our national interest.

India has been a strong advocate of the principle of Common but Differentiated Responsibility in the matter of global actions to protect environment and also that national circumstances need to be factored in for arriving at any durable agreement related to climate.

At the commencement of negotiations in Kigali, the developed countries had suggested one single common baseline years for production and consumption of HFCs for developing countries i.e. 2017-2018-2019 and freeze year as 2021. However, various developing countries proposed as many as six different baselines range from 2017 to 2030, and freeze year-ranging from 2021 to 2031.

India piloted realistic baseline of 2024-2026 for developing countries and which protects India's interests. As per the agreement reached in Kigali, India will freeze its manufacturing and consumption of HFCs in 2028

and start reducing it from 2032 to 2047 with reference to the baseline years 2024, 2025 and 2026. The Freeze year is subject to technology review and could be further deferred to 2030. The agreement facilitates adequate carbon space for growth on domestic industry while minimizing the cost to the economy during the transition period.

India had consistently taken a position that the baseline and freeze years should be at such a future date which allows for growth of economy while minimizing cost to the economy. The Indian delegation also had steadfastly raised the issues of Intellectual Property Rights of non-HFC technologies, the high cost of these technologies and resultant cost to economy in transitioning away from HFCs.

In the Kigali Amendment, it has been agreed that the developing countries will have two set of baselines - one for the early movers in which case it will be 2020-2021-2022 and the other for those whose national circumstances were different and the manufacturing of the HFCs and consumption in whose case was still rising in the absence of clear alternative technologies. In case of such countries the agreed baseline years are 2024, 2025 and 2026.

At the same time, it has also been agreed that the developed countries will reduce their production and consumption of HFCs by 70 per cent in 2029. India will complete its phase down in four steps from 2032 onwards with cumulative reduction of 10 per cent in 2032, 20 per cent in 2037, 30 per cent in 2042 and 85 per cent in 2047.

The Montreal Protocol had no arrangement till date to incentivise improvement in energy efficiency in case of use of new refrigerant and technology. On India's initiative, it was agreed in Kigali that the Multilateral Fund under the Montreal Protocol will pay for maintaining or increasing the energy efficiency with new technology. Funding for R&D and servicing sector in developing countries has also been included in the agreed solutions on finance.

The success of negotiations at Kigali is a result of the spirit of collective action, accommodation and flexibility by all the parties to ensure the best possible outcome which addresses the needs of all countries and leads to maximum climate benefits. '

I am happy to inform the House that India has been able to secure an agreement that provides adequate space for growth of our economy while providing adequate time for industry to shift to sustainable alternatives in the

interest of environment. The agreed arrangements will minimize the cost to consumers in transitioning away from HFCs and provide for domestic innovation to develop in the sector of new generation refrigerants and related technologies.

I am thankful to the hon. Prime Minister under whose constant and active guidance we approached the negotiations with a positive, flexible and constructive mindset and were able to convince the international community of the interests of India and similarly placed developing countries. The resultant agreement reflects the global ambition and at the same time allows us to take necessary steps for protection of environment and our domestic economy in a longer time frame.

I wish to thank the august House for giving me this opportunity and look forward to receiving further guidance from the hon. Members.

(Ends)

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please circulate the copies to everybody. Only after that I will adjourn the House.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, can we seek clarifications?

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Not today. If you want clarifications, we can have it later. Not now because I extended the time by two minutes until the speech was over, and you agreed.

The House stands adjourned to meet at 11.00 a.m. tomorrow, the 7th February, 2017.

...

The House then adjourned at four minutes past six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 7th February, 2017.